VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

ABHYAAS MAINS

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II)/GENERAL STUDIES (Paper-II) (2929)

निर्धारित समय: **तीन घंटे**
Time Allowed: ***Three Hours***

अधिकतम अंक: **250**
Maximum Marks: ***250***

सामान्य अनुदेश

इस प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका में 55+1 पृष्ठ हैं। प्रश्न-पत्र, क्यू.सी.ए. पुस्तिका के अंत में संलग्न है, जो अलग (वियोज्य) किया जा सकता है और उम्मीदवार परीक्षा के उपरांत अपने साथ ले जा सकते हैं।

रफ कार्य के लिए, इस पुस्तिका के अंत में खाली पृष्ठ दिया गया है।

पुस्तिका प्राप्त होने पर, कृपया यह जांच कर लें कि इस क्यू.सी.ए. पुस्तिका में कोई कमी न हो, फटा हुआ पृष्ठ न हो अथवा कोई पृष्ठ गायब न हो इत्यादि। यदि ऐसा हो, तो इसके बदले नई क्यू.सी.ए. पुस्तिका प्राप्त कर लें।

General Instructions

This Question-Cum-Answer (QCA) Booklet contains 55+1 pages. Question Paper in detachable form is available at the end of the QCA Booklet which can be taken away by the candidate after examination.

For rough work, blank page has been provided at the end of this Booklet.

On receipt of the Booklet, please check that this QCA Booklet does not have any shortcomings, torn or missing pages etc. If, so, get it replaced with a fresh QCA Booklet.

(उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा/To be filled by the Candidate)

पंजीकरण सं./Registration No. : 01046611

अभ्यर्थी का नाम/Name of Student : खेतदान चारण

माध्यम: हिंदी/अंग्रेजी
Medium: Hindi/English

हिन्दी

तारीख
Date

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II)
GENERAL STUDIES (Paper II)

केंद्र
Centre

MN

निरीक्षक के हस्ताक्षर
Invigilator's Signature

VISIONIAS

	महत्वपूर्ण अनुदेश **उम्मीदवारों को नीचे उल्लिखित निर्देश सावधानी से पढ़ लेने चाहिए। किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने पर उम्मीदवारों को मिलने वाले अंकों में कटौती, उम्मीदवारी रद्द या आयोग के परवर्ती परीक्षाओं के लिए वर्जित करने इत्यादि के रूप में दण्डित किया जा सकता है।**	**Important Instructions** **Candidates should read the undermentioned instructions carefully. Violation of any of the following instructions may entail penalty in the form of deduction of marks, cancellation of candidature, debarment from further Examination of the Commission etc.**
1	(क) अपना पंजीकरण सं. एवं अन्य विवरण केवल प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) में उम्मीदवार के लिए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। (ख) इस पुस्तिका में अन्यत्र कहीं भी अपना नाम, पंजीकरण सं., मोबाइल नं., पता अथवा प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) संख्या न लिखें जिससे आपकी पहचान का खुलासा हो।	(a) Write your Registration Number and other details only in the space provided in the Question-Cum-Answer (QCA) Booklet for candidates. (b) Do not disclose your identity in any manner such as, by writing your Name, Registration number, Mobile number, Address, Question-Cum-Answer (QCA) Booklet No. etc. elsewhere in the Booklet
2	अपनी प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में कहीं भी प्रश्नों के वास्तविक उत्तर के अतिरिक्त कुछ न लिखें जैसे कि कोई कविता/दोहा, अभद्र या अपमानजनक अभिव्यक्ति इत्यादि और न ही कोई ऐसा चिन्ह/निशान बनाएं जिसका उत्तर से सम्बन्ध न हो।	Do not write in the QCA Booklet anything other than the actual answer such as couplet, obscene, abusive expression etc., nor put any sign/mark having no relevance to the answer.
3	परीक्षक को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी प्रार्थना/धमकी भरी बातें न लिखें।	Do not make any direct/indirect appeal/threat to the examiner.
4	उत्तर अस्पष्ट अथवा गंदी लिखावट में न लिखें। इस प्रकार के उत्तर का मूल्यांकन नहीं भी किया जा सकता है।	Do not write answers in bad/illegible handwriting. Such answers may not be evaluated.
5	उत्तर स्याही में ही लिखें। उत्तर लिखने के लिए पेंसिल का उपयोग न करें, हालांकि आरेख, चित्र इत्यादि बनाने के लिए पेंसिल का उपयोग किया जा सकता है।	Write answers in ink only. Do not use pencil for writing the answers. However, pencil may be used for drawing diagrams, sketches, etc.
6	प्रवेश पत्र में उल्लेख किए गए माध्यम के अलावा अन्य किसी माध्यम में उत्तर न लिखें। अधिकृत और अनधिकृत की मिली जुली भाषा का भी उपयोग न करें।	Do not write answers in medium other than the authorized medium in the Admission Certificate. Do not use mixed language either i.e. authorize and unauthorized media together for writing answers.
7	प्रश्नों के उत्तर ठीक उसके नीचे दिए गए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर लिखे गए उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।	Write answer at the specific space (right below the question) only. Answers written elsewhere at unspecified places in the booklet shall not be evaluated.
8	यदि आप अपने किसी उत्तर को रद्द करना चाहते हैं तो उसे पेन से काट दें तथा उस पर "रद्द" लिख दें, अन्यथा उसका मूल्यांकन किया जा सकता है।	If you wish to cancel any work, draw your pen through it and write "Cancelled" across it, otherwise it may be valued.

VISION IAS

कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use	कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use
परीक्षक के हस्ताक्षर Signature of Examiner(s)	

प्राप्तांक के विवरण (परीक्षक द्वारा भरा जाए)/ Marks Details (To be filled by the Examiner(s))

प्रश्न सं. Q. No.	अंक Marks		प्रश्न सं. Q. No.	अंक Marks	
1			11		
2			12		
3			13		
4			14		
5			15		
6			16		
7			17		
8			18		
9			19		
10			20		
उप-योग (A) Subtotal (A)			उप-योग (B) Subtotal (B)		
सकल योग (A+B) / GRAND TOTAL (A+B)					

VISION IAS

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

ABHYAAS MAINS

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II)/GENERAL STUDIES (Paper-II) (2929)

निर्धारित समय: **तीन** घंटे Time Allowed: **Three** Hours	अधिकतम अंक: **250** Maximum Marks: **250**

प्रश्न-पत्र संबंधी विशेष अनुदेश

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

*कुल **बीस** प्रश्न दिए गए हैं जो **हिंदी** और **अंग्रेजी** दोनों में छपे हैं।*

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्न संख्या 1 से 10 तक का उत्तर 150 शब्दों में तथा प्रश्न संख्या 11 से 20 तक का उत्तर 250 शब्दों में दीजिए।

प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखिए।

प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ भाग को पूर्णतः काट दीजिए।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions.

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.*

All questions are compulsory.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Answers to Questions No. 1 to 10 should be in 150 words, whereas answers to Questions No. 11 to 20 should be in 250 words.

Keep the word limit indicated in the questions in mind.

Any page or portion of the page left blank in the Questions-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

VISION IAS

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS

1. असहमति की अभिव्यक्ति संसद के कामकाज का केंद्रीय तत्व है। इसके आलोक में, भारत की संसदीय व्यवस्था में विपक्ष के नेता (LoP) की भूमिका पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Expression of dissent is central to the functioning of the Parliament. In light of this, discuss the role of the Leader of Opposition (LoP) in India's parliamentary system. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

असहमति की अभिव्यक्ति लोकतंत्र का एक अभिलाक्षणिक लक्षण है। जिसे अरस्तू ने भी "हो सकता है मैं आपके विचारों से असहमत हूँ लेकिन आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करता हूँ" कहकर की है।

संसदीय कामकाज का प्रमुख तत्व कैसे - ?

- मंत्रिपरिषदीय निरकुंशता को रोकता है।
- नए विचारों को प्रदान करता है।
- कामकाज की संस्कृति में सहमति जन्यता को लाने में सहायक।
- संसदीय भ्रष्टाचार को रोकता है।
- संसदीय सरकार के लोकतान्त्रिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला सिद्धांत है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

विपक्ष की भूमिका :- संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप 10% seat वाले दल को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना जाता है।

① बिल का विरोध :-
└ निरंकुश प्रवृति की धाराओ का विरोध करने का कार्य करता है।

Ex. GST क्षतिपूर्ति वाद में राज्यों के लिए विपक्ष द्वारा विरोध।

② विधायी प्रक्रिया के पालन में ⇒ money bill के साथ आधार बिल के समय विरोध।

③ तानाशाही प्रवृत्ति पर नियंत्रण ⇒ मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाकर

④ बिल में सुधार की सिफारिशें करना।

⑤ संसदीय जवाबदेहिता - प्रश्नकाल, ध्यानकर्षण प्रस्ताव द्वारा

लेकिन कभी-कभी अनावश्यक विरोध, राजनीतिक घेराव तथा walk out culture के द्वारा संसदीय कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए प्रभावी विपक्ष नेता के साथ-साथ कुशल नेतृत्व व नैतिक पक्ष का समावेशन अनिवार्य है।

2. न्यायिक प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी का समावेशन न्याय प्रदायगी के संदर्भ में पहुंच, क्षमता और दक्षता को किस प्रकार बढ़ा सकता है? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

How can the integration of technology into judicial processes enhance accessibility, capability, and efficiency in justice delivery? (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

" न्याय केवल अन्याय का नही होना नही है बल्कि समय पर न्याय होना " न्याय कहलाता है।

न्यायिक प्रक्रिया में प्रौद्योगिक समावेशन के लाभ :-

१. पहुँच में वृद्धि

↳ न्यायिक अदालतों तक आसानी से पहुँच (ex e-Court filing

↳ दूरस्थ गवाहों द्वारा tele conference के द्वारा गवाही देने में सक्षमता।

↳ पुराने केसों की फाईलिंग के कारण डिजिटल एक्सेस में वृद्धि होगी।

↳ प्रौद्योगिकी से कानून शब्दावली का अनुवादन आसानी से → जन-जन की भाषा (हिन्दी) मे न्यायिक आदेश का प्रचार → पहुँच मे वृद्धि

↳ संवेदनशील मामलों में सुरक्षा के खतरें को कम करेगा ex, Court मे Jail से गवाही

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

क्षमता में वृद्धि

↳ Court के लिए कागजी आवश्यकता को कम करेगा

↳ Bar एसोसिएशन के वकीलों की ऑनलाइन उपस्थिति से वकील हायर करने मे आसानी

↳ न्यायिक डेटा सग्रंहण & भण्डारण मे वृद्धि

↳ न्यायिक जवाबदेहिता को बढावा देगा।

दक्षता पर प्रभाव → न्यायिक जवाबदेहिता → दक्षता को बढावा देगा।

दक्षता पर प्रभाव → आँकड़ो का प्रबन्धन & त्वरित गवाही → जल्दी Case निपटान

दक्षता पर प्रभाव ↓ कॉलेजियम में भी पारदर्शिता लाएगा

लेकिन कुछ न्यायिक बाधाए
- → डिजिटल डिवाइड
- → न्यायालय में कोई का अभाव
- → न्यायिक बुनियादी अवसरंचना की कमी
- ← जनता की कम जागरुकता

Way Forward

- न्यायिक स्टैक पर कार्य किया जाए।
- अनुपालन पर बल।
- ADR प्रणाली को बढावा।
- न्यायिक समावेशन (महिला & दलित) को बढावा देवे।

3. भारत के उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीकृत सत्ता एवं क्षेत्रीय स्वायत्तता को जटिल रूप से संतुलित करके भारत के संघवाद में अद्वितीय विषमता को बनाए रखा है। न्यायालय द्वारा दिए गए प्रासंगिक पूर्ववर्ती निर्णयों की सहायता से चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

The Supreme Court of India has upheld unique asymmetry in India's federalism by intricately balancing centralized authority and regional autonomy. Discuss with the help of relevant case laws. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी v/s राजनारायण केस में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को व्यापक अर्थ मे बताते हुए केन्द्रीकृत सत्ता व क्षेत्रीय स्वायतता के मध्य ~~सम~~ समन्वय बनाए रखा

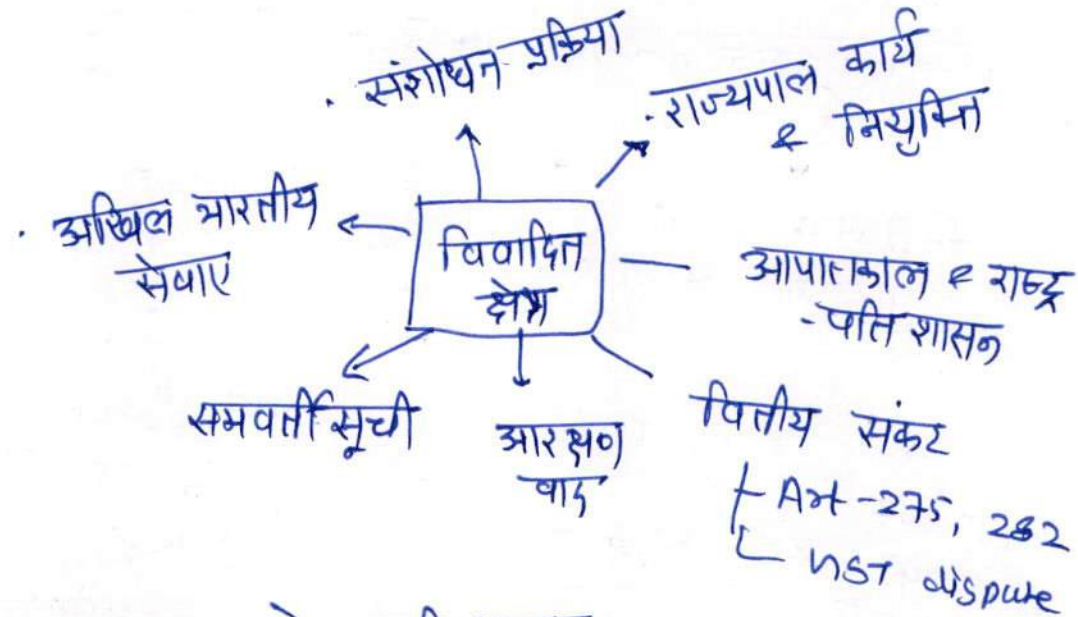

राज्यपाल से संबंधित वाद -

↳ नबाम रेबिया case - Art. 161 का प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श से।

GST dispute वाद मे सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि GST Council का निर्णय बाध्यकारी नही।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

97th CA सहकारी समितियों से अधिनियम में राज्य की परामर्श नहीं ली गई। इसलिए उसके कुछ भाग को असंवैधानिक घोषित किया / संविधान (संशोधन) में केन्द्रीकरण को रोका।

आरक्षण याद
↳ मराठा आरक्षण बिल → राज्य को निश्चित मापदंड पुरा करते हुए स्थानीय आरक्षण का विकल्प

वित्तीय संकट - Art-275 & 285 वित्तीय अनुदान के लिए निरन्तर वित्त आयोग की गठन की सिफारिश।

हालांकि सर्वोच्च न्यायालय सहकारी संघवाद की स्थापना में सहायक रहा है लेकिन अभी भी ऐसे कई क्षेत्र है जिनमें सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका अनिवार्य है।

4. भारत में अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) NCSC
Evaluate the effectiveness of the National Commission for Scheduled Castes in safeguarding the interests of the Scheduled Castes in India. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। जिसका गठन निम्न उद्देश्य के लिए किया गया था।

किए गए कार्य

↳ अनु. जाति के संवैधानिक प्रावधानों के मूल्यांकन के लिए कार्य करना।

↳ NCSC का मुख्य कार्य अनु. जाति के कल्याण के लिए सरकार से सिफारिशें करना।

↳ सरकारी कार्यों, योजनाओं का निरीक्षण करना।

↳ योजना का जन प्रचार करना।

↳ राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना।

↳ SC. कल्याण के नए क्षेत्रों की खोज करना।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

लेकिन कुछ समस्याए बनी हुई है-

↳ सिफारिशें केवल सलाहकारी है - बाध्यकारी नही।

↳ नियमित रूप से बैठकों का अभाव।

↳ समय पर नियुक्ति नही।

↳ अंतर मंत्रालयी & अंतर आयोग समन्वय का अभाव

↳ मानवाधिकार आयोग & NCSC & NCST में समन्वय नही।

way forword :-

↳ समय पर नियुक्ति की जाए।

↳ आयोगों का डिजिटलीकरण किया जाए।

↳ आयोग का बहुस्तरीय वार्ता मंच से जुड़ाव

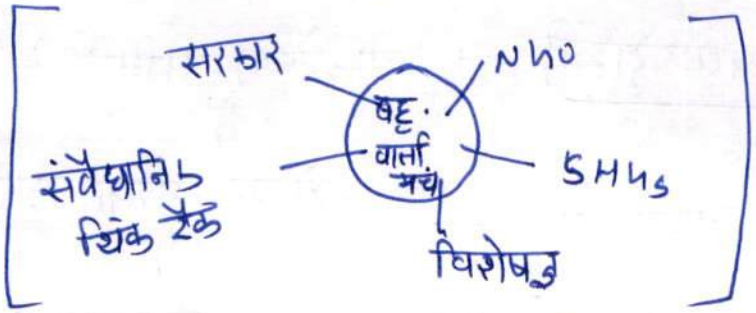

↳ SC जनकल्याणकारी योजनाओ का प्रभावी क्रियान्वयन

5. संसदीय समितियों के माध्यम से विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करना भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की पहचान रही है। टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Executive accountability to the legislature through Parliamentary Committees has been the hallmark of the Indian political system. Comment. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

Ans

ऐशियन डेमोक्रेटिक रिफोर्म की रिपोर्ट ने संसदीय समितियों को सौपें जाने वाले विधेयकों की घटती समस्या को उजागर करके इसे विस्तृत चर्चा का विषय बना दिया है।

स्वतंत्रता के पश्चात संसदीय समितियों को भारतीय शासन व्यवस्था का प्रमुख अंग समझा जाता था। अधिकांश बिल समितियों को सौपे जाते थे।

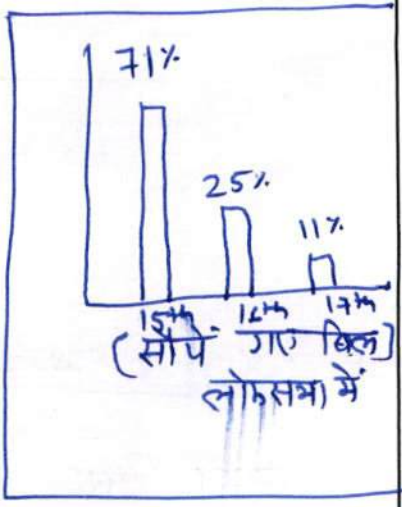

कार्यपालिका जवाबदेहिता कैसे सुनिश्चित करती है -

① वित्तीय जवाबदेहिता — लोकलेखा समिति के द्वारा
↳ भ्रष्टाचार का उजागर करती है
↳ लेखा परीक्षा करके
↳ मितव्ययता के सिद्धान्त का पालन करवाती है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

② विधायी जवाबदेहिता ⇒ मंत्रिपरिषद द्वारा लाए गए सरकारी विधेयक की प्रवर समितियों द्वारा जाँच & कटौती प्रस्ताव लाया जाना।

③ राजनीतिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना।
↳ PSU's समिति → PSU's के कार्यों के लेखा परीक्षा के द्वारा
⇓
प्रगति का मूल्यांकन

⑤ प्रगति समीक्षा & मूल्यांकन ⇒ कार्यपालिका के कार्यों के लेखांकन की CAG द्वारा निर्मित रिपोर्ट की अंतिम जाँच (लोकलेखा समिति) करके सुनिश्चित जवाबदेहिता करती है।

लेकिन कुछ समस्याएं हैं

- सलाहकारी प्रवृति
- दण्ड देने की शक्ति नहीं
- तदर्थ समितियों का कम गठन
- मंत्रिपरिषदीय निरकुंशता

अत: संसदीय जवाबदेहीता बनाए रखने के लिए संसदीय समितियों की भूमिका महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य है।

6. भारत नागरिक चार्टर को किस प्रकार शासन में सुधार करने और नागरिकों को सशक्त बनाने का एक शक्तिशाली उपकरण बना सकता है? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

How can India make Citizens' Charter a powerful tool for improving governance and empowering citizens? (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

नागरिक अधिकार पत्र सरकारी संस्थानों द्वारा नागरिकों को गुणवतापूर्ण सेवा समयबद्ध रूप में उचित शिकायत निवारण तंत्र सहित उपलब्ध करवाने की गारंटी देता है।

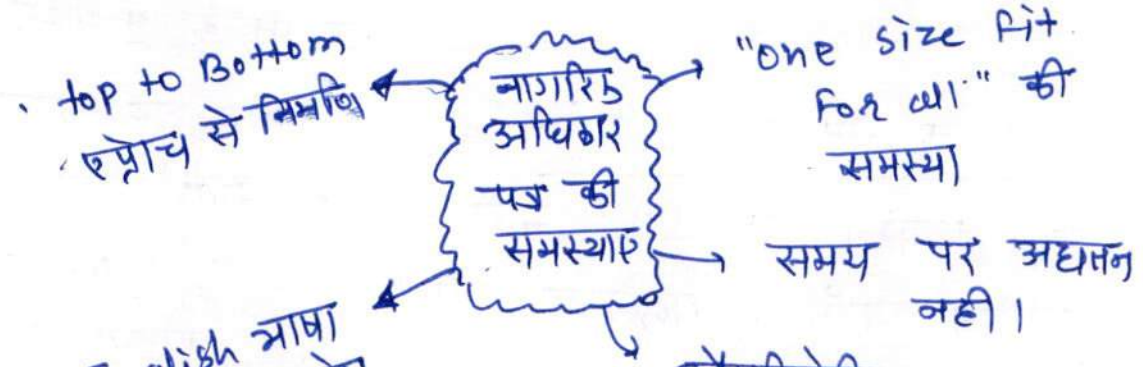

किस प्रकार शक्तिशाली उपकरण बना सकता है?

① शासन में सुधार का → ना. अ. पत्र जनभागीदारी को बढ़ावा देगा

लक्षित सेवा वितरण

पारदर्शिता का प्रवेश

शिकायत निवारण तंत्र

गुणवत्ता पूर्ण सेवा वितरण में सहायक

प्रशासनिक जवाबदेही को बढ़ावा

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

नागरिक सशक्त कैसे ?

→ जन सतर्कता में वृद्धि

→ प्रशासन पर नियंत्रण का विकल्प प्रदान करेगा।

→ लाभार्थी के बजाय जनता को शासन का भागीदार बनाएगा।

way forward (कैसे बनाया जाए) :-

① स्थानीय (त्रिभाषा फार्मूले) भाषा में अनुवादन

② विभाग विशेष अलग-2 ना. अधिकार पत्र निर्माण

③ सेवोत्तम मॉडल

2nd ARC सुझाव
- नागरिक सक्रियता
- नागरिक सुझाव
- पारदर्शिता
- जवाबदेहिता
- अनुक्रियाशीलता
- समावेशन
- उत्तरदायित्व

इस प्रकार ना. अधिकार पत्र सुशासन निर्माण का प्रमुख घटक बन सकता है।

7. कॉर्पोरेट दानकर्ता भारत में समग्र विकास को सुविधाजनक बनाने में NGOs की किस प्रकार सहायता करते हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
How do corporate donors aid NGOs in facilitating holistic development in India? (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

वर्ल्ड बैंक के अनुसार NGO's वे गैर लाभकारी संस्थान होते है जो जनकल्याण के क्षेत्र में कार्यरत होते है।

कॉर्पोरेट दानकर्ता का NGO's में योगदान :-

↳ वे निगम जो NGO's को वित्तीय सहायता प्रदान करवाते है उन्हे कॉर्पोरेट दानकर्ता कहा जाता है। ex. रतन टाटा,

कॉर्पोरेट दान से फायदें :-

↳ NGO's कार्य क्षेत्र का विस्तार

↳ ग्रामीण क्षेत्र तक connectivity बढेगी।

→ विभिन्न क्षेत्रों के लिए NGO's अपना कार्य आक्रामक रूप से कर सकते है।

Ex. Go Green कार्यक्रम (शही NGO's का)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

समाज कल्याण मे वृद्धि →

(ex. अक्षयपात्र, मिलन NGO's विस्तृत Fund के कारण करने मे सक्षम

NGO's द्वारा चलने वाले अधिकार आधारित आंदोलनो में वृद्धि होगी

(ex. MKSS → मजदूरो के लिए।
नाज फाउंडेशन → ट्रांसजेंडर के लिए।

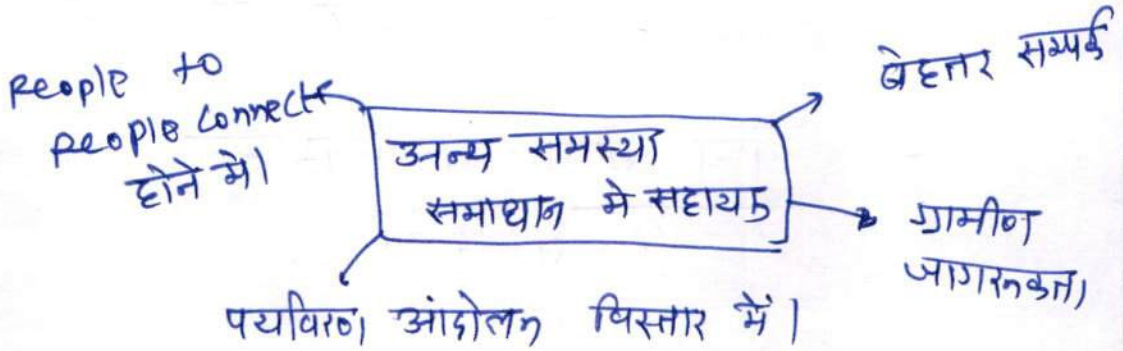

कोर्पोरेट दानकर्ता के साथ समस्याएं :- अत्यधिक कम

- फण्ड प्रदान करने के बाद NGO's की भूमिका पर संदेह
- प्रशासनिक जटिलता
- CSR का प्रयोग नही।

क्या किया जाए ?

- Social impact Bond जारी किए जाए।
- zero coupan zero principal bond को बढावा
- NGO's का प्रभाव मूल्यांकन (अजित डोवाल)

8. POCSO अधिनियम के गुणों के बावजूद, इसकी मौजूदा कमियों को दूर करने के लिए क्या इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Despite its merits, should the POCSO Act be revisited to correct the existing inadequacies? (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

POCSO की कमियाँ -

- लिंग संवेदनशील
- अस्पष्ट परिभाषा
  - (स्पर्श करना)
    - HC. द्वारा अलग व्याख्या
- आयु सीमा अत्यधिक कम
  - (12 से 18 वर्ष)
- "सुधार के विकल्प"
  - पुनर्विचार किया जाए
  - बालक की परिभाषा में बदलाव
  - स्पष्ट परिभाषा की जरूरत

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

9. चीन द्वारा वैश्विक स्तर पर रणनीतिक बंदरगाहों के अधिग्रहण के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों एवं आर्थिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
China's acquisition of strategic ports globally has significant implications for international trade routes and economic relations. Discuss. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

चीन निरंतर अपनी विस्तारवादी नीति के कारण रणनीतिक बंदरगाहों का अधिग्रहण करने मे प्रयास रत है।

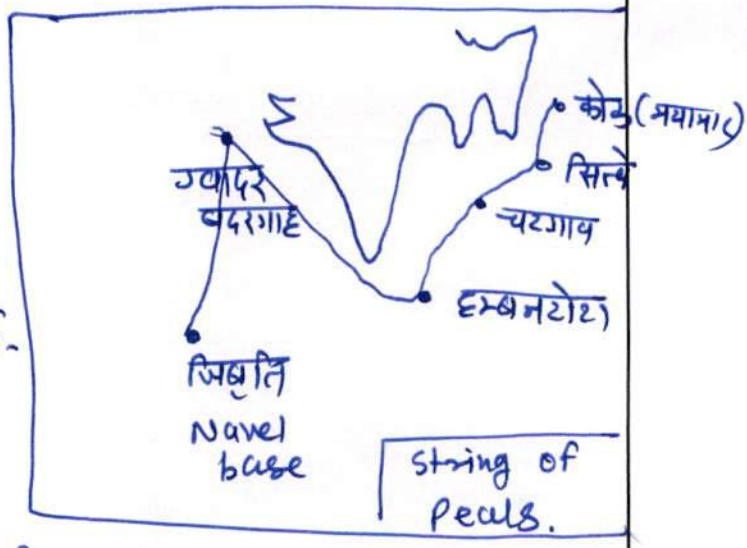

व्यापार मार्ग & आर्थिक संबंधो के लिए निहितार्थ:-

(i) चीन के लिए
- आर्थिक विस्तार
- नए बाजारों की खोज
- निवेश करके राजनीतिक नियंत्रण की स्थापना करना
- Belt & Road initiative के क्रियान्वयन मे सहायक
- भारत को ~~भा~~ चुनौती
- USA trade war में जीतने का प्रयास।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत के लिए निहितार्थ — हिन्द महासागर में नेट सुरक्षा प्रोवाइडर बनने पर रोड

- सामरिक महत्व पर नियंत्रण
- दक्षिण एशिया में व्यापार चुनौती
- String of pearls से घेराव

विश्व के लिए निहितार्थ

- समुद्री व्यापार मे बाधा
- नए trade war की संभावना
- समुद्री संसाधनों के लिए टकराव
- शक्ति असंतुलन की उत्पत्ति

अन्य देशों & भारत के उपाय :-

① Neeklace of daimond की नीति

② Coastal Surveillance Radar (मारीशस, सेशेल्स में)

③ दक्षिण अफ्रीकी देशों से सहयोग

④ उत्तर-दक्षिण आर्थिक गलियारा, IMEC, भारत व जापान द्वारा निर्मित कॉरीडोर ।

अतः उत्पन्न इस शक्ति असंतुलन संकट के लिए UNCLOS & UN की भूमिका को बढावा दिया जाना चाहिए ।

10. विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के मुख्य कार्य क्या हैं? बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान पर इसकी हालिया संधि से भारत को क्या लाभ होगा? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
What are the main functions of the World Intellectual Property Organization (WIPO)? How will its recent treaty on intellectual property, genetic resources and associated traditional knowledge benefit India? (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन

~~बौद्धिक~~ UN की एक विशेष एजेंसी है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कार्य करती है।

प्रमुख कार्य → बौद्धिक नियमों का अवलोकन
→ उनके प्रभावों का मूल्यांकन
→ Report जारी करना ⇒ "Global Innovation Index"

संधि से भारत को लाभ :-

① भारतीय पारम्परिक वस्तुओं (हल्दी, नीम) इत्यादी को बौद्धिक अधिकारों की सुरक्षा में प्राथमिकता।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

(2) भारतीय पारम्परिक ज्ञान का विस्तार

(3) बौद्धिक सम्पदा सुरक्षा में छवि का निर्माण
└ WTO के TRIPS समझौते का पालन।

(4) भारतीय औषधियों पर खोज व अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा।

(5) आयुर्वेद - यूनानी, होम्योपैथी, सैंध (आयुष) प्रणाली को विकास का अवसर मिलेगा।

(6) भारतीय औषधियों के लिए विस्तृत बाजार मिलने की संभावना में वृद्धि होगी।

(7) पारम्परिक चिकित्सा प्रणाली का विस्तार सम्भावनाशील है।

11. यद्यपि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) भ्रष्टाचार से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, फिर भी इसकी कार्यप्रणाली की प्रायः पक्षपातपूर्ण होने तथा संघीय भावना के विरुद्ध कार्य करने के लिए आलोचना की जाती है। समुचित उदाहरणों की मदद से चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

While the Central Bureau of Investigation (CBI) plays a crucial role in combating corruption, its functioning is often criticized for being partisan and acting against the federal spirit. Discuss with the help of suitable examples. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

CBI एक वैधानिक संस्थान है जिसका गठन दिल्ली पुलिस अधिनियम के द्वारा भ्रष्टाचार से निपटने के उद्देश्य के लिए किया गया है।

भ्रष्टाचार मे महत्वपूर्ण भूमिका :-

- केन्द्र स्तर पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखता है।
- CVC के साथ मिलकर कार्य करता है।
- राज्य स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियो पर भ्रष्टाचार की जाँच मे कार्य

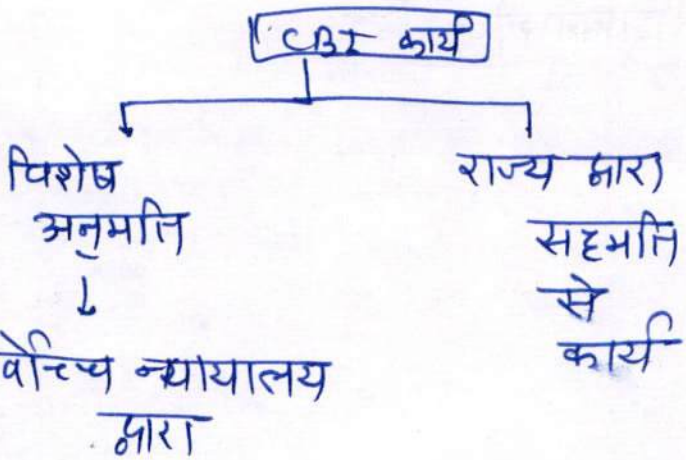

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

लेकिन वर्तमान मे संघीय भावना के विरुद्ध कार्य करने के आरोप क्योंकि

- केन्द्रीय उपकरण के रूप मे प्रयोग
- संस्थान का राजनीतिकरण
- विपक्षीय राज्य सरकार में अनावश्यक रूप से CBI जाँच
  - Ex. बंगाल में
- पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कार्य
  - भ्रष्टाचार पोषित सिद्धि पर अत्यधिक कम
  - राजनीतिक गठबन्धन का आरोप।

Way forward:-

① संस्थान में न्यायिक हस्तक्षेप बढाया जाए।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

② CBI सदस्य नियुक्ति में
विपक्ष नेता + PM + CJI की सलाह

③ प्रभावी मूल्यांकन को बढ़ावा दिया जाए।

.12. भारत में राज्यपाल प्रायः अपनी संवैधानिक भूमिका का अतिक्रमण करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर प्रभावी ढंग से कार्य करने में विफल रहते हैं। टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Governors in India often overstep their constitutional role and fail to act effectively when needed. Comment. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत ने संघीय शासन व्यवस्था को अपनाते हुए कनाडा संविधान की तरह राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया है जिसमें राज्यपाल केन्द्रीय प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।

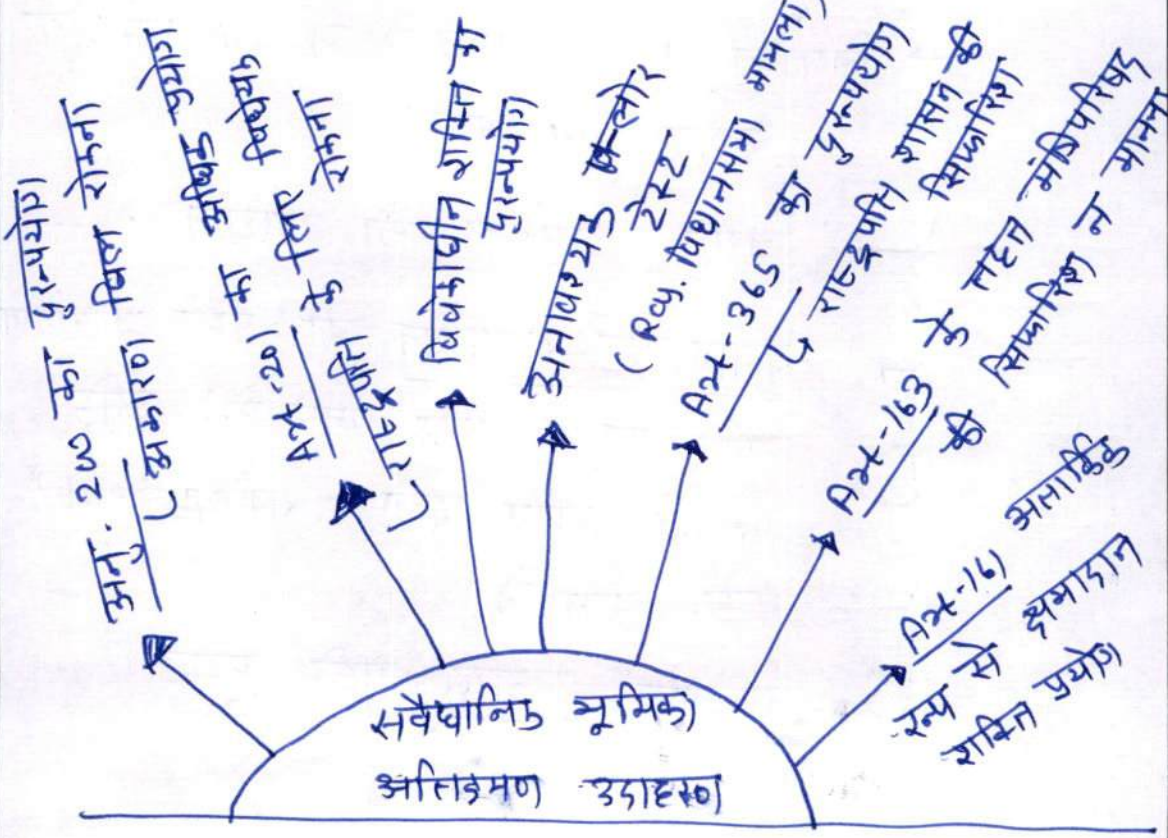

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उपर्युक्त अनेक उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट होता है कि उनके कार्य-प्रणाली में अनेक त्रुटियाँ पाई जाती हैं।

सुधार के लिए किए जाने योग्य सिफारिशें :-

① सरकारिया आयोग & पुंछी आयोग की सिफारिशें

- नियुक्ति में मुख्यमंत्रियों से सिफारिश व सलाह ली जाए।
- नियत कार्यकाल का प्रावधान
- चुनाव पूर्व गठबन्धन का पहले प्राथमिकता दी जाए (सरकार बनाने मे) उसके पश्चात अन्य दलो (सर्वाधिक Seat) के क्रम मे।
- राष्ट्रपति अकारण नहीं हटाए।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

② NCRWC - 2002 द्वारा की गई सिफारिशों का ध्यान दिया जाए।

③ सर्वोच्च न्यायलयों के निर्णयों का पालन
└ Ex. नबाम रेबिया वाद

④ सहकारी संघवाद को बढावा
→ अंतर राज्य परिषद (Art-262) द्वारा
→ राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा
→ Zonal Council के माध्यम से।

इस प्रकार राज्यपाल को राज्य तथा केन्द्र दोनो के मध्य संबंधो के निर्माण का प्रमुख तत्व माना जाता है। इसके सुधार के माध्यम से ही शासन के सभी स्तरो में समन्वय साधा जा सकता है जो विकसित भारत @2047 तक ले कर जाएगा।

13. भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में ही लोकतांत्रिक सिद्धांतों का अनुपालन किया जाता है, लेकिन उनकी निर्वाचन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भिन्नताएं विद्यमान हैं। दोनों देशों की निर्वाचन पद्धतियों में मुख्य भिन्नताएं क्या हैं? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Both India and the USA adhere to democratic principles but their electoral systems exhibit significant differences. What are the key differences in electoral practices between the two countries? (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत व USA दोनो लोकतांत्रिक राष्ट्र है जो स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति के रूप में कार्यपालिका प्रमुख, उपराष्ट्रपति का पद, तथा विधि के शासन व विधि के सम्यक् प्रक्रिया को अपने संविधान मे स्वीकार करते है।

लेकिन निर्वाचन व्यवस्था में अत्यधिक अंतर देखने को मिलता है -

① भारत संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाता है जबकि USA अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाता है।

संसदीय
- de-jure → राष्ट्रपति
- de-facto → प्रधानमंत्री

अध्यक्षात्मक → राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

निर्वाचन प्रणाली - USA सीनेट में 100 सदस्य होते हैं। प्रत्येक का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है।

↳ ऊपरी सदन में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व मिलता है।

↓

50 राज्य → 100 सदस्य

लेकिन भारत में राज्यसभा में राज्यों को अलग-अलग प्रतिनिधित्व मिलता है।

USA मंत्रिपरिषद में दोहरी सदस्यता नहीं पाई जाती है जबकि भारतीय मंत्रिपरिषद में दोहरी सदस्यता पाई जाती है।

निर्वाचक मण्डल में अंतर

राष्ट्रपति का निर्वाचक मण्डल
↓
अप्रत्यक्ष निर्वाचन

→ USA राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

सांसद निर्वाचन के लिए भारत में First Past the Post पद्धति जबकि USA सीनेट सदस्यों में इसका अभाव है।

भारतीय निर्वाचन प्रणाली में विभिन्न ~~सदस्यों~~ दलों के लिए चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाता है जबकि USA चुनावों में कोई चुनाव चिन्ह नहीं होते है (भारत का नवाचार)

इस प्रकार USA व भारत के चुनावी प्रणाली, निर्वाचक मण्डल तथा सदन की अवधि & कार्यप्रणाली में अत्यधिक अंतर देखने को मिलता है।

14. आप इस दृष्टिकोण से किस हद तक सहमत हैं कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने भारत में पर्यावरणीय न्याय सुनिश्चित करने के अपने उद्देश्य की पूर्ति की है? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
How far do you agree with the view that the National Green Tribunal (NGT) has met its objective of ensuring environmental justice in India? (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)

एक वैधानिक संस्था है जिसका गठन राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम -2010 के तहत किया गया है। यह अधिनियम पर्यावरण क्षेत्र में कार्य करने के लिए गठित किया गया था।

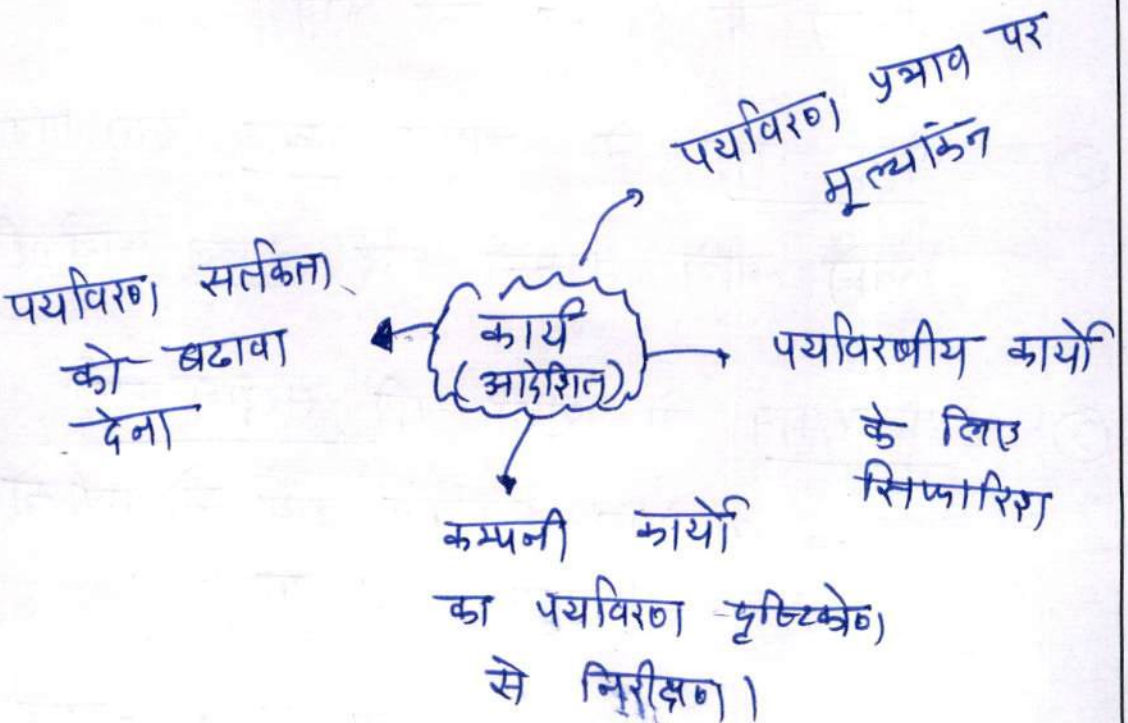

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

इस अधिकरण को सिविल न्यायलय के समान निम्न शक्तियाँ प्राप्त है।

→ समन जारी करने की।
→ गवाह बुलाने की शक्ति।
→ मंत्रालयो से तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने की शक्ति

NGT की सफलताए :-

① NGT द्वारा ग्रीन क्रेकर्स को बढावा तथा न्यायालय की सहायता से पटाखों पर प्रतिबंध लगवाने का कार्य।

② गंगा नदी मे चमड़ा उद्योग द्वारा मिलाई जाने वाले प्रदूषकों पर सख्त कार्यवाही।

③ राजस्थान मे लूणी नदी संरक्षण कार्य
→ बालोतरा कारखाना तथा गंदे पानी को मिलाया जाता था।
↓
कम्पनियो को बंद करवाने की भूमिका

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

NHT में समस्याएं :-

- अधिकरण के पास वित्तीय स्वायत्तता का अभाव।
- स्वयं के संसाधन की कमी।
  - मानव संसाधन का अभाव (उच्च रिक्तियाँ)
- अंतर-एजेंसी समन्वय का अभाव
- अधिकरण का जन प्रचार अधिक नहीं।

Way forward

- वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जाए।
  - सजा प्रावधान करने का विकल्प दिया जाए।
- राजनीतिकरण को रोका जाए।
- Political- NHT- Corporate Nexus को तोड़ा जाए।

15. यद्यपि पंचायती राज संस्थाएं (PRIs) प्रतिस्पर्धी राजनीति के लिए एक मंच बन गई हैं, किंतु इनका नियोजन एवं सेवा वितरण की एजेंसी के रूप में उद्भव नहीं हुआ है। क्यों? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Though Panchayati Raj Institutions (PRIs) have become a platform for competitive politics, they have not emerged as an agency of planning and service delivery. Why? (Answer in 250 words)15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

" जनता की आवाज ईश्वर की आवाज है।
पंचायत की आवाज जनता की आवाज है।।

• महात्मा गाँधी •

73वें संविधान संशोधन के परचात पंचायती राज संस्थाओ ने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के विकास मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्रतिस्पर्धी राजनीति का मंच कैसे ?

- महिला आरक्षण (1/3) ⇓ महिला को राजनीति में प्रवेश
- ग्रामीण क्षेत्र मे जातिगत राजनीति को बढावा
- SC&ST के आरक्षण से राजनीति का दलितकरण किया
- ग्रामीण संगठनो के विकास से ग्रामीण राजनीति को संघर्षात्मक & प्रतिस्पर्धात्मक बनाया

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

किंतु सेवा वितरण & नियोजन ऐजेंसी के रूप में क्यों नहीं हो पाया ?

(a) 3F — की कमी

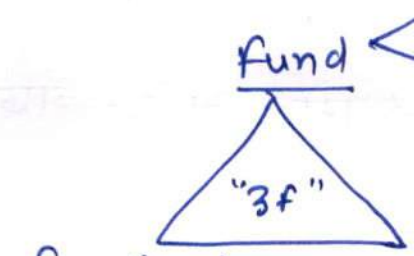

Fund → un-tied fund कम
वित्त आयोग द्वारा कम सिफारिश (14th वित्त. आयोग से पूर्व)

Functionaries → रिक्तियाँ अधिक
→ ग्रामीण भ्रष्टाचार

Function → कार्यों में विविधता कम

(b) ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच का गठबन्धन

(3) राज्य सरकारों के विरोधाभासी कानून
(ex. हरियाणा का ग्राम विकास एजेंसी कानून

(4) प्रशासन पर अति निर्भरता → प्रत्येक खर्च, वित्त आवरन & उपयोग के लिए अनुमति अनिवार्य

(5) राज्य की कम रूचि
(विषय का आवरन नहीं किया गया)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

(6) OBC का आरक्षण अनिवार्य शर्त नहीं।

(7) राज्य सरकारों द्वारा अभी तक विधायकों, पार्षदों को इससे नहीं जोड़ा गया।

फिर क्या किया जाए ?

(1) कर लागू करने की शक्तियां प्रदान की जाए।
  └ स्थानीय कर - पथ कर, मनोरंजन कर, आवास निर्माण कर

(2) 3-F में सुधार किया जाए।
  ├ रिक्तियाँ भरी जाए (⅓ रिक्ति)

(3) सरपंच पति अवधारणा को खत्म किया जाए।
  → महिला सशक्तिकरण (शिक्षा, Skill, सा-सुधार)

(4) पंचायतों का डिजिटलीकरण, online attendance ग्राम विकास अधिकारी)

(5) स्वविवेकी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाना चाहिए।

Q6. ई-गवर्नेंस में अंतरसंचालनीयता (इंटरऑपरेबिलिटी) से आप क्या समझते हैं? विभिन्न ई-गवर्नेंस प्रणालियों की अंतरसंचालनीयता एवं एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
What do you understand by interoperability in e-governance? What steps have been taken by the government to ensure interoperability and integration of various e-governance systems? (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

" ई-गवर्नेंस एक ऐसी प्रणाली है जिसमें महज कम्प्यूटर के कुछ कुंजियों द्वारा लाखों चेहरों पर मुस्कान लाई जा सकती है।"
• PM. मोदी •

ई-गवर्नेंस की अंतर संचालनीयता :- यह एक ऐसी विशेषता को इंगित करता है जो ई.गवर्नेंस को लचीलापन बनाने तथा उसे एक रूप से दूसरे रूप में, एक विभाग से दूसरे विभाग, एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी तथा एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में संचालन के में ई-गवर्नेंस को सक्षम बनाता है।

उम्मीदवारें को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

ई-गवर्नेंस के प्रकार
- गवर्मेंट टू गवर्मेंट
- गवर्मेंट टू सिटीजन
- गवर्मेंट टू बिजनेस

एकीकरण के लिए किए गए प्रयास :-

① गवर्मेंट टू गवर्मेंट ⇒
- 'मेघदूत' सभी जिला कार्यालयों को जोड़ा गया।

② गवर्मेंट टू बिजनेस :-
- e-procurement.com सरकारी खरीद में निविदा दाताओं को आमंत्रण
- दस्तावेज प्रसंस्करण के लिए e-गवर्मेंस
- Online खरीद को बढ़ावा दिया जाना
- सरस मेला, ई-सरस ⇒ SHG's के लिए सहायता App
- संकल्प & समाधान पोर्टल ⇒ MSME के लिए
- NHO के लिए दर्पण पोर्टल
- बिजनेस नहीं - PNbsg@minutes.com

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

गवर्मेंट टू सिटीजन :-

- शिक्षा
  - PM-ई-विद्या
  - दीक्षा पोर्टल
  - स्वयं पोर्टल
- स्वास्थ्य
  - ई-संजीवनी
  - digi Locker
  - COVIN APP
- अन्य
  - संकल्प पोर्टल
  - ASEEM पोर्टल (रोजगार)

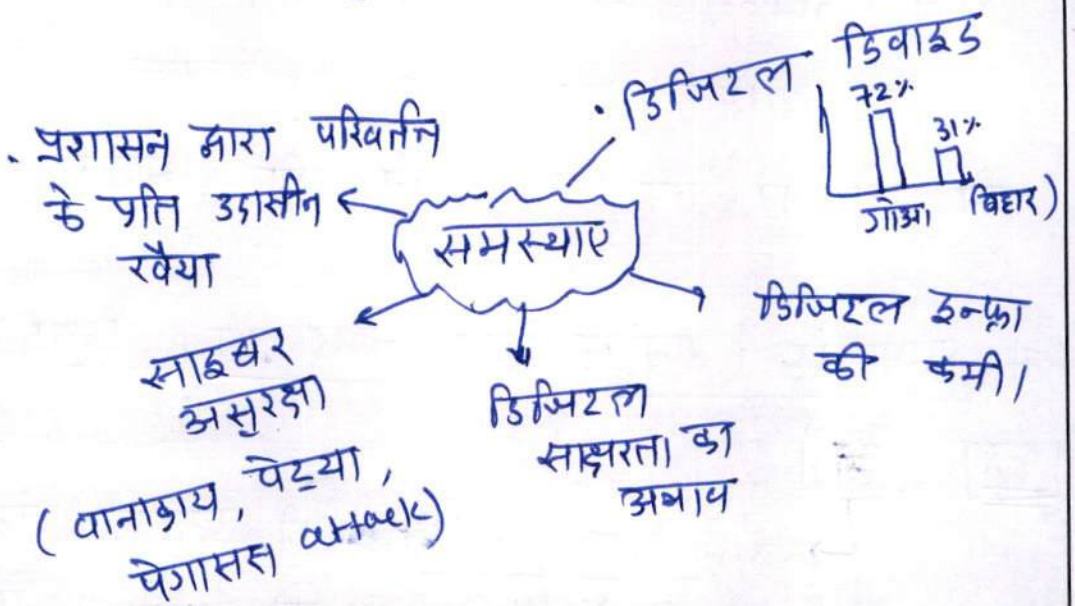

हालांकि ई-गवर्नेंस में कुछ प्रारम्भिक लागत & अन्य समस्याएं है लेकिन डिजिटल साक्षरता अभियान, पब्लिक डिजिटल इन्फ्रा तथा साइबर सुरक्षित वातावरण का निर्माण करके ई-गवर्नेंस को विकास का इंजन बनाया जा सकता है।

17. जब भारत में महिलाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की बात आती है, तब अधिकार-आधारित विमर्श को न केवल सामाजिक मानदंडों द्वारा बल्कि कानूनी मानदंडों द्वारा भी बड़े पैमाने पर नजरअंदाज किया गया है। विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए) 15

When it comes to sexual and reproductive health of women in India, rights-based discourse has largely been bypassed not just by the societal norms but also by the legal norms. Discuss. (Answer in 250 words)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

NCRB आँकड़ो के अनुसार प्रत्येक एक घंटे मे भारत मे 4 महिलाए यौन उत्पीड़न का शिकार बनती है।" ऐसी प्रवृत्ति वर्तमान के बंगाल, UP उत्पीड़न हत्याकाण्ड मे विशेष रूप मे देखने को मिलती है।

सामाजिक मानदण्ड को नजर अंदाज किया गया है।

Ex

- सामाजिक समानता की स्थापना नहीं की गई है → (महिला को प्राथमिकता नहीं)
  - POCSO Act लिंग तटस्थ कानून है।
- सामाजिक स्टीरियोटाइप को महत्व
- महिला को घरेलू कार्यो तक सीमित
  - Total Fertility Rate में वृद्धि का कारक

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

↳ यौन शिक्षा का अभाव (जस्टिस वर्मा कमेटी)

↳ प्रजनन के समय ग्रामीण क्षेत्र में का प्रयोग

इसी प्रकार कानूनी मानदण्डो को नजर अंदाज :-

↳ महिला सुरक्षा अधिकार विमर्श ने • कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधि. 2013 को विधेयित करवा लिया लेकिन इस कानून मे भी खामिया रही।

- आंतरिक शिकायत समिति का समय पर गठन नही।

↳ सोशल मीडिया के युग मे प्रभावी सोशल मीडिया विनियामक का अभाव

(USA सीनेट प्रति दिन 37% महिलाए अनावश्यक & अनजान रूप मे नग्नता का शिकार होती है।

↳ कानूनी आंदोलनो में तकनीकी लूपहोल पर ध्यान नही दिया गया।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

way forword

① जया जेटली समिति

अधिकार आधारित विमर्श मे निम्न जोड़े
→ विवाह उम्र 18 से 21 की जाए।
→ यौन शिक्षा दी जाए।

② प्रजनन स्वास्थ्य सुधार हेतु
→ अस्पताल व ग्रामीण दूरी को कम करे।
→ doctor/patient अनुपात को बढ़ाए।

③ तकनीकी सुधार को बढ़ावा

④ नारी विमर्श आंदोलनो का सशक्तिकरण

⑤ सरकार के प्रयास
→ सुरक्षित साइबर वातावरण
→ यौन पाद निपटान मे तीव्रता
→ यौन शिक्षा को बढ़ावा

इस प्रकार महिला सशक्तिकरण को अधिकार आधारित विमर्श के माध्यम से बढ़ावा देकर अधिक सुरक्षित, देखभाल पूर्ण, न्यायपूर्ण व शांतिपूर्ण राष्ट्र का निर्माण किया जाना चाहिए।

18. पिछले कुछ वर्षों में भारत टीकाकरण कवरेज को बढ़ाने में कितना प्रभावी रहा है? देश में टीकाकरण के प्रयासों को प्रभावित करने वाली चुनौतियां कौन-सी हैं? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

How effective has India been in enhancing immunization coverage over the years? What challenges continue to affect immunization efforts in the country? (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत ने स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन तथा बेहतर स्वास्थ्य परिणाम प्राप्ति करने के लिए टीकाकरण को प्रमुख साधन के रूप में अपनाया है।

मिशन इन्द्र धनुष के तहत भारत ने वैक्सीनेशन को सभी के लिए उम्र आधारित मानकों पर पूर्ण किया है जिसकी सफलता अत्यधिक रही है।

टीकाकरण में उत्पन चुनौतियाँ :-

① टीका आपूर्ति में समस्या :-

↳ अधिकांश टीकों की आयात के माध्यम से आपूर्ति की ~~जाति~~ जाती है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

• टीके निर्माण मे घरेलू स्तर पर आवश्यक निर्माण सामग्री का अभाव है।

सामाजिक जनधारणाएं

- टीकों का विरोध
- होम्योपैथी के प्रति सुझाव
- ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच का अभाव
- ~~चिकित्सकीय~~ चिकित्सालयों मे समय अत्यधिक लगना।
- टीकों की संख्या अधिक होने के कारण प्रारम्भ के टीके लग जाते है लेकिन 5 वर्ष के पश्चात वाले टीको के प्रति लापरवाही अत्यधिक बरतना।

टीकों के लेकर उत्पन्न भ्रम -

- Cowshield को लेकर

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

सुधार के उपाय

① आयुष कल्याण केन्द्रों की स्थापना

② मोबाईल मेडीकल यूनिटों का निर्माण

③ R&D पर खर्च
WHO के अनुसार GDP का 6% तक बढाया जाए।

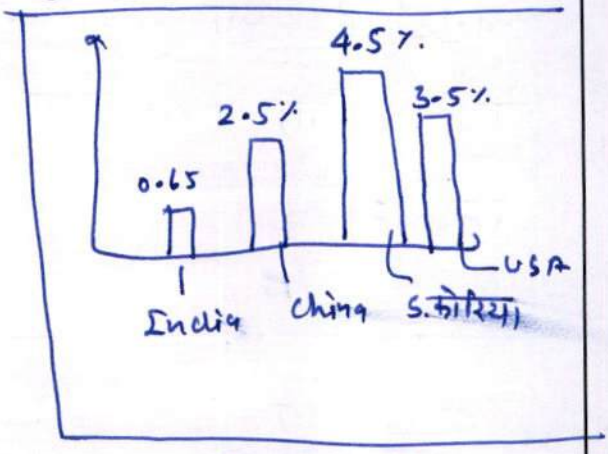

④ वैक्सीन के प्रति जनधारणा निर्माण का कार्य किया जाए। डॉक्टर सुरक्षा को प्रोत्साहन

⑤ महिला का शिक्षाकरण, सशक्तिकरण व स्वास्थ्य मानकों में सुधार किया जाना चाहिए।

अतः उपरोक्त सुझावों के माध्यम से टीकाकरण प्रतिशत में व्यापक वृद्धि की जा सकती है जो एक युवा भारत व स्वस्थ भारत का निर्माण कर सके।

19. भारत ने G20 की अपनी अध्यक्षता का उपयोग वैश्विक दक्षिण की आवाज़ को केंद्रीय मंच पर लाने के लिए किया है। अफ्रीका के विशेष संदर्भ के साथ चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
India used its Presidency of the G20 to bring the voice of the Global South to the centre stage. Discuss with special reference to Africa. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

वैश्विक दक्षिण दक्षिणी देशों (अल्पविकसित, विकासशील, अविकसित) का एक समूह है जो वैश्विक राजनीति में कम प्रतिस्पर्धी व सीमित समावेशन के अभाव का शिकार रहा है।

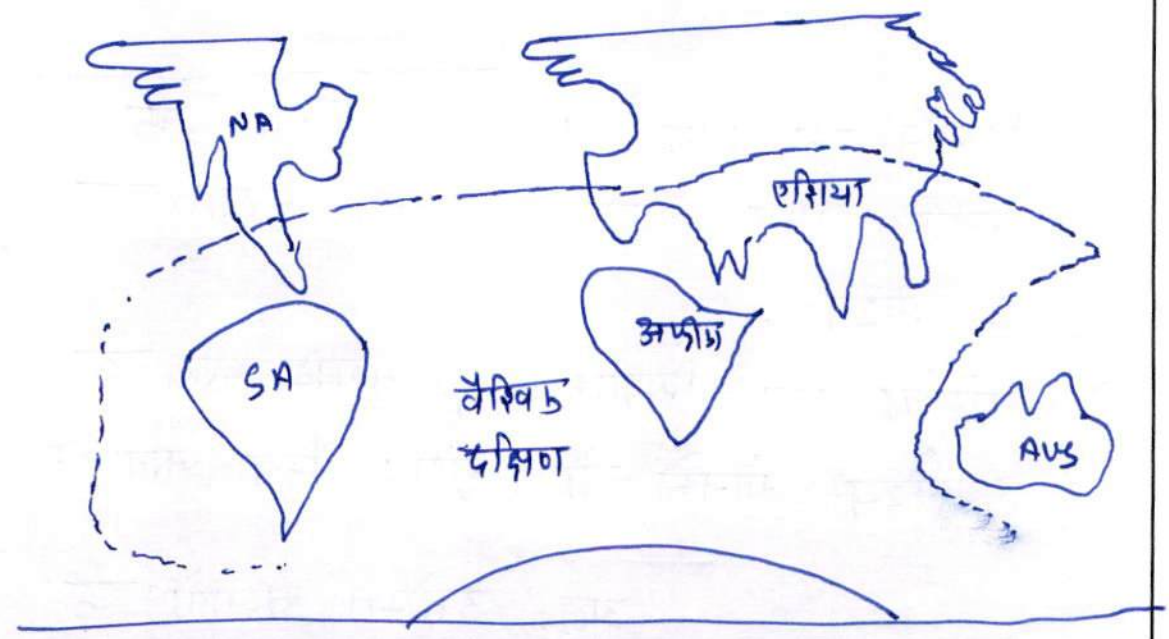

भारत ने G-20 का प्रयोग वै.दक्षिण के लिए
↳ G-20 में अफ्रीकी यूनियन को सदस्यता दिलाने हेतु।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

- अफ्रीका समुद्री क्षेत्र मे सुरक्षा हेतू ब्लू इकोनॉमी के लिए चेन्नई दिशा-निर्देशो के पालन पर समर्थन।
- अफ्रीका के मरुस्थलीकरण की समस्या को ध्यान मे रखते हुए दिल्ली घोषणा पत्र में 2040 तक 50% मरुस्थलीकरण रोकने पर समर्थन व गाँधीनगर सूचना मंच का निर्माण।
- अफ्रीकी क्षेत्र मे मानवीय विकास के लिए व व्यापार वृद्धि के लिए बेसिक न्यूनतम कर तथा Two pillar plan को स्वीकार्य किया गया।
- Global biofuel Alliance का गठन
  - अफ्रीकी बायो ईंधन को बढावा मिलेगा।
- IMEC कॉरिडोर से व्यापार मे वृद्धि जिसे भविष्य मे अफ्रीका के लिए विस्तार की संभावना।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

~~इसके साथ साथ~~

इस प्रकार भारत ने G-20 में अफ्रीका को महत्व दिया जो कि निम्न रूप मे लाभकारी होगा

भारत के लिए

- UNSC मे सदस्यता दावा मजबूत
- G-20 मे सदस्य – रणनीतिक महत्व
- नेट सुरक्षा प्रदाता बनेगा
- वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व
- दक्षिण अफ्रीका मे निवेश सम्भावना वृद्धि

G-20 के लिए

- विस्तृत समावेशन
- 85% विश्व GDP
- 70% जनसंख्या
- # सुधार मे सहायता आसानी से।

अतः G-20 सम्मेलन में भारत ने वैश्विक दक्षिण के नेता के रूप मे कार्य करते हुए व अफ्रीका को केन्द्र में रखते हुए सफल आयोजक का कार्य किया है।

20. पिछले दशक में भारत और UAE के बीच संबंधों में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
India's relationship with the UAE has witnessed a remarkable expansion across various domains in the last decade. Discuss. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत व UAE संबंध एशियाई देशो की मिशाल बने हुए है जो 21वी शताब्दी में अन्य राष्ट्रो के लिए उदाहरण बने हुए है।

संबंध

① आर्थिक संबंध ⇒
↳ हाल ही मे काम्प्रिहेंसिव इकोनोमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) किया गया (2022 मे)
→ Free trade Agreement & double taxation Agreement किया हुआ है।

② डायस्पोरा संबंध ⇒ UAE भारतीय मजदूरो का पश्चिम एशिया में सऊदी अरब के बाद दूसरा प्रमुख गंतव्य स्थल है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

क्रिकेट डिप्लोमेसी ⇒ IPL का सफल आयोजन UAE मे किया गया था।

सामरिक संबंध ⇒ I_2U_2 का सदस्य
(~~इस~~- इजरायल, इंडिया, UAE, USA)

└ UNSC मे भारत की सदस्यता का समर्थन

राजनीतिक संबंध ⇒ विदेश मंत्री S.जयशंकर का UAE दौरा तथा UAE राजनेताओं का भारत में किए गए दौरे।

निजी निवेश → भारतीय व्यापारियो के लिए दुबई निवेश का प्रमुख केन्द्र बन कर उभरा है।

लेकिन UAE के साथ कुछ राजनीतिक व श्रम कानून संबंधित विवाद प्रचलित है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

विवाद के विषय

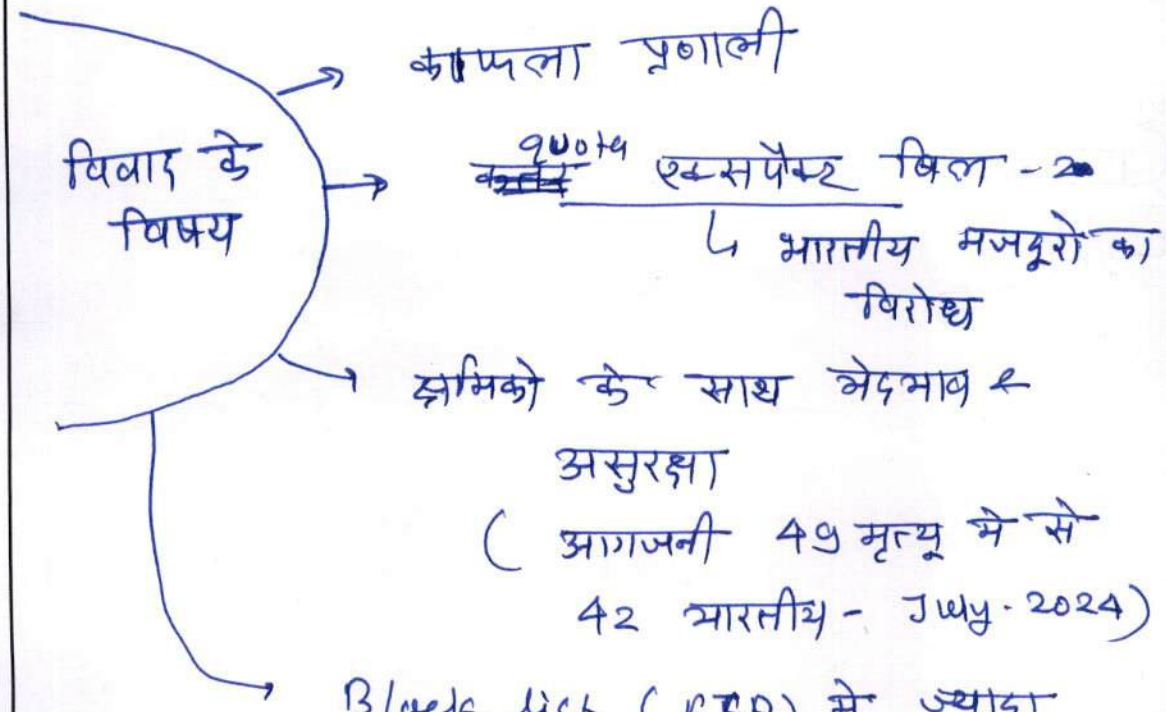

- → काफला प्रणाली
- → ~~कोटा~~ quota एक्सपैट्स बिल - 2
  - ↳ भारतीय मजदूरों का विरोध
- → श्रमिको के साथ भेदभाव & असुरक्षा
  (आगजनी 49 मृत्यु मे से 42 भारतीय - July - 2024)
- → Black list (FAA) मे ज्यादा वस्तुए।

हालांकि विदेशी संबंधो में कुछ समस्याए ~~[illegible]~~ स्वत: & प्राकृतिक रूप में पाई जाती है लेकिन इन्हे 3R (रिकगनाइज़ रेस्पेक्ट - रिवेल्युएट) व 5-स (सुरक्षा - शांति - सहयोग - सम्मान व समृद्धि) दृष्टिकोण के द्वारा बढावा देकर पुन: ऊर्जावान संबंध बनाए जाने चाहिए।

SPACE FOR ROUGH WORK